possible for the Government to meet demand for foodgrains.

मालपा त्रासदी से प्रभावित लोगों का पुनर्वास

328. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री 17 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 272 के ए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रूद्र प्रयाग (चमोली जिले) की उखीमठ तहसील के 20 से अधिक गांवों को असुरक्षित घोषित किया गया है तथा उनके स्थान पर नये गांवों के निर्माण हेतु आयुक्त, गढ़वाल द्वारा गुप्तकाशी के पास भूमि उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उखीमठ त्रासदी से पीड़ित इन गांवों के पुनर्निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के साथ चर्चा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिए इस संबंध में उससे कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया।

दलहन प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन

329. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री 10 दिसम्बर, 1998 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1266 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने जिलों में दलहन प्रोत्साहन योजना लागू करने का विचार है;

(ख) क्या इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इस योजना को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, विशेषकर उत्तराखंड/उत्तरांचल में भी लागू करने का विचार है जहां लोबिया, उड़द, सोयाबीन, तूर आदि दलहन फसलें प्रचुर मात्रा में उगायी जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) तिलहन तथा दलहन प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना की स्कीम 295 जिलों को कवर करते हुए 24 राज्यों और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से सितम्बर, 1996 में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत 44.905 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्राप्त किया गया है। प्रस्ताव में बीज वितरण एवं सिंचाई (डीजल सप्लाई पर राजसहायता) पर राजसहायता की अनुमति देने के लिए 1996-97 से 2001-2002 तक ग्रीष्म कालीन दलहन उत्पादन के विशेष कार्यक्रम हेतु सहायता शामिल थी। लेकिन प्रस्ताव राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के मानदण्डों के अनुसार नहीं था, अतः इसे स्वीकार नहीं किया गया। बहरहाल हमने 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को निम्न राशियां निर्मुक्त की हैं:—

वर्ष	निर्मुक्त राशि
1996-97	713.50 लाख रुपये
1997-98	877.25 लाख रुपये
1998-99	550.00 लाख रुपये (आज तक)

(ग) और (घ) राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 49 जिले कवर किए गए हैं। इनमें से निम्न जिले पहाड़ी क्षेत्रों में हैं:—

1. नैनीताल
2. पिथौरागढ़
3. पौड़ी गढ़वाल
4. उधम सिंह नगर
5. चम्पावत

"नैफेड" के प्रबंध निदेशक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

330. **श्री रमा शंकर कौशिक:**
श्री ईश दत्त यादव:
प्रो॰ रामगोपाल यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "नैफेड" के प्रबंध निदेशक पर लगे भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोपों की जांच कराई है या कराने का विचार कर रही है;

(ख) क्या नैफेड कर्मचारी यूनियन ने भी माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है और उक्त प्रबंध निदेशक को हटाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो प्रबंध निदेशक पर लगे भ्रष्टाचार सहित सभी आरोपों की जांच एवं उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (ग) नैफेड कर्मचारी संघ ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें नैफेड में धन के दुर्विनियोजन का आरोप लगाया गया तथा उक्त प्रबंध निदेशक को हटाने की मांग की गई। विभाग द्वारा की गई जांच तथा इस मामले में प्राप्त कुछ अन्य शिकायतों के आधार पर यह मामला आगे और जांच के लिये सी०बी०आई० को भेजा गया था। सी०बी०आई० ने कथित अनियमितताओं के संबंध में नैफेड के कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध एक मामला पंजीकृत किया है।

उक्त प्रबंध निदेशक की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन मिलने तक के लिये अध्यक्ष, नैफेड द्वारा पूर्णतया अस्थाई आधार पर की गई थी। इस बीच उसने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी। यद्यपि, उक्त पद पर उनकी नियुक्ति को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने स्वीकृति नहीं दी, तथापि वह न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश के कारण इस पद पर बने रहे। अन्ततः रिटयाचिका खारिज कर दी गई। रिट याचिका को खारिज किये जाने के मद्देनजर उक्त प्रबंध निदेशक को 01.02.1999 से नैफेड से कार्य मुक्त कर दिया गया।

Fund for Central Agricultural University

331. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the fund for the Central Agricultural University has not been released for this year i.e. 1998-99;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) what is the progress of construction of buildings in other States where different faculties are to be opened; and

(d) whether the Management Board of the Central Agricultural University has asked the concerned State Governments to lend building temporarily for opening/ commencing the faculties?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURAL (SHRI SOMPAL): (a) and (b) Funds have been released worth Rs. 12.00 crores for the Central Agricultural University on 22.1.1999.

(c) Construction works of Central Agricultural University have started in three out of the four college campuses, i.e. College of Agriculture, Imphal (Manipur), College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Selesih (Mizoram) and College of Fisheries, Lembuchera (Tripura) for which agreements were signed in 1997. The first phase of construction of the three colleges costing about Rs. 35 crores is likely to be over by March, 2001. The constructions of Girls Hostel and Administrative-cum-library-cum-museum Block at Imphal are at the advance stages of completion.

The renovation of old buildings located in the Veterinary College campus has been completed and college has started functioning therein with effect from March, 1998. Construction of new Animal Science Complex at Imphal was completed.

(d) The University requested the Govt. of Tripura and space was provided for opening Fishery College in Tripura.

The University is approaching the Govt. of Meghalaya to provide temporary space to start the College of Home Science at Tura.

The State Govt. has been approached by the University for handing over site for P.G. College at Barapani.